



छत्तीसगढ़

लेक्चरर

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीजीएसएसबी/व्यापम)

अर्थशास्त्र विषय

Part - A

भाग - 3

INDEX

S.NO.	CHAPTER	P.NO.
ECONOMICS		
1.	अपस्फीति (Deflation)	1
2.	मौद्रिक संस्थाएँ (Monetary Institutions)	4
3.	केन्द्रीय बैंक (Central Bank)	6
4.	वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)	8
5.	भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI)	9
6.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त (International Trade Theory)	12
7.	व्यापार की शर्तें (Terms of Trade - TOT)	18
8.	विदेशी विनिमय दर (Foreign Exchange Rate)	23
9.	भुगतान संतुलन (BOP) की परिभाषा	26
10.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF)	32
11.	विश्व बैंक (World Bank)	34
12.	आर्थिक विकास (Economic Development)	37
13.	आर्थिक विकास के मॉडल	39
14.	भारत में जनसंख्या एवं संरचना	41
15.	राष्ट्रीय आय (National Income)	43
16.	गरीबी (Poverty)	49
17.	बेरोजगारी (Unemployment)	52
18.	रोजगार नीति (Employment Policy)	56
19.	कृषि (Agriculture)	61
20.	औद्योगिक नीति (Industrial Policy)	67
21.	लघु एवं कुटीर उद्योग	73
22.	निर्यात संवर्द्धन (Export Promotion)	76
23.	सामाजिक सुरक्षा (Social Security)	79
24.	श्रम कल्याण (Labour Welfare)	82

25.	भारतीय आर्थिक नियोजन (Indian Economic Planning)	85
26.	सांख्यिकी (Statistics)	92
27.	आँकड़ों के प्रकार एवं संकलन	97
28.	आँकड़ों का सारणीयन (Data Tabulation)	100
29.	सांख्यिकीय श्रेणियाँ (Statistical Series)	102
30.	सांख्यिकीय श्रेणियों के माप	114
31.	अपकिरण	130

अपस्फीति (Deflation)

1. अपस्फीति (Deflation) की परिभाषा (Definition)

परिभाषा

अपस्फीति वह आर्थिक स्थिति है जिसमें सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) में लगातार कमी आती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है।

सरल परिभाषा

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तो उसे अपस्फीति कहते हैं।

2. अपस्फीति का अर्थ (Meaning)

- ✓ अपस्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य घटते हैं।
- ✓ मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है।
- ✓ मांग एवं निवेश कम होने लगते हैं।
- ✓ लंबे समय तक अपस्फीति रहने से आर्थिक मंदी आ सकती है।

3. अपस्फीति के कारण (Causes of Deflation)

(1) मुद्रा आपूर्ति में कमी

अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होने से मांग घट जाती है।

(2) निवेश में कमी

उद्योगों द्वारा निवेश कम करने से उत्पादन एवं रोजगार प्रभावित होते हैं।

(3) उपभोक्ता मांग में कमी

जब लोग भविष्य में और कम कीमतों की अपेक्षा करते हैं, तो खरीदारी टाल देते हैं।

(4) अत्यधिक कर एवं सख्त मौद्रिक नीति

अधिक कर तथा ऊँची ब्याज दरें मांग को कम कर देती हैं।

4. अपस्फीति के प्रभाव (Effects of Deflation)

(1) उत्पादन में कमी

कम मांग के कारण उद्योग उत्पादन घटा देते हैं।

(2) बेरोजगारी

उद्योगों में उत्पादन कम होने से श्रमिकों की छुट्टनी होती है।

(3) निवेश में गिरावट

लाभ कम होने के कारण नए निवेश में कमी आती है।

(4) ऋणियों पर प्रतिकूल प्रभाव

मुद्रा का मूल्य बढ़ने से ऋण चुकाने का वास्तविक भार बढ़ जाता है।

5. अपस्फीति के नियंत्रण के उपाय

(1) मुद्रा प्रसार नीति अपनाना

केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम करके तथा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर मांग को बढ़ाता है।

(2) सरकारी व्यय बढ़ाना

सार्वजनिक निवेश बढ़ाने से रोजगार एवं आय में वृद्धि होती है।

(3) करों में कमी

करों में कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है।

(4) सस्ती ऋण नीति

कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने से निवेश एवं उत्पादन बढ़ता है।

6. मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति में अंतर (Difference between Inflation and Deflation)

आधार	मुद्रास्फीति	अपस्फीति
अर्थ	सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि	सामान्य मूल्य स्तर में कमी
मुद्रा का मूल्य	घटता है	बढ़ता है
क्रय शक्ति	कम होती है	बढ़ती है
मांग	बढ़ती है	घटती है
रोजगार	प्रारंभ में बढ़ सकता है	घटता है
मौद्रिक नीति	संकुचनात्मक नीति अपनाई जाती है	प्रसारात्मक नीति अपनाई जाती है
मुख्य समस्या	महंगाई	मंदी एवं बेरोजगारी

(Important Facts)

- ✓ Inflation = General Price Level ↑
- ✓ Deflation = General Price Level ↓
- ✓ Inflation ⇒ Purchasing Power ↓
- ✓ Deflation ⇒ Purchasing Power ↑
- ✓ Demand-Pull Inflation = मांग अधिक, पूर्ति कम।
- ✓ Cost-Push Inflation = लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ना।
- ✓ Hyper Inflation = अत्यधिक तीव्र मुद्रास्फीति।

-
- ✓ मुद्रास्फीति नियंत्रण = Repo↑, CRR↑, SLR↑, OMO Sale।
 - ✓ अपस्फीति नियंत्रण = Repo↓, CRR↓, OMO Purchase।
 - ✓ Inflation = महँगाई + मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी।
 - ✓ Deflation = कीमतों में गिरावट + मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि।
 - ✓ Inflation → Debtor Gains, Creditor Loses.
 - ✓ Deflation → Creditor Gains, Debtor Loses.
 - ✓ Demand-Pull = Excess Demand.
 - ✓ Cost-Push = Rising Cost of Production.
 - ✓ Hyper Inflation = अत्यधिक मूल्य वृद्धि।
 - ✓ Inflation Control = Contractionary Monetary Policy.
 - ✓ Deflation Control = Expansionary Monetary Policy.



मौद्रिक संस्थाएँ (Monetary Institutions)

1. मौद्रिक संस्थाएँ (Monetary Institutions) की परिभाषा (Definition)

परिभाषा

वे संस्थाएँ जो किसी देश में मुद्रा (Money), साख (Credit), बैंकिंग प्रणाली तथा वित्तीय प्रवाह (Financial Flow) का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करती हैं, मौद्रिक संस्थाएँ (Monetary Institutions) कहलाती हैं।

सरल परिभाषा

मुद्रा के निर्माण, वितरण, विनियमन, ऋण व्यवस्था एवं भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाली संस्थाओं को मौद्रिक संस्थाएँ कहा जाता है।

2. मौद्रिक संस्थाओं का अर्थ (Meaning)

- ✓ ये संस्थाएँ अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं।
- ✓ इनका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
- ✓ ये बचत को निवेश में परिवर्तित करती हैं।
- ✓ बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाती हैं।

3. मौद्रिक संस्थाओं के प्रकार (Types of Monetary Institutions)

(1) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

देश का सर्वोच्च बैंक, जो मुद्रा एवं मौद्रिक नीति का संचालन करता है।

उदाहरण

- भारत – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- अमेरिका – Federal Reserve
- इंग्लैंड – Bank of England

(2) वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks)

जनता से जमा स्वीकार कर ऋण प्रदान करने वाले बैंक।

उदाहरण

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

(3) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।

(4) विकास बैंक (Development Banks)

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

उदाहरण

- NABARD
- SIDBI
- EXIM Bank

4. मौद्रिक संस्थाओं के प्रमुख कार्य (Functions of Monetary Institutions)

(1) मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित करना

ये संस्थाएँ अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती हैं ताकि मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके।

(2) साख (Credit) का नियमन

बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा एवं ब्याज दरों को नियंत्रित करके आर्थिक संतुलन बनाए रखा जाता है।

(3) बचत को प्रोत्साहित करना

जनता की बचत को बैंकिंग प्रणाली में लाकर उसे उत्पादक निवेश में परिवर्तित किया जाता है।

(4) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराकर उद्योग, कृषि एवं व्यापार के विकास में सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

1. केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition)

डी. किंले (D. Kinley) के अनुसार

"केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था का शीर्ष नियंत्रक होती है।"

डी. कॉक्स (De Kock) के अनुसार

"केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मुद्रा व्यवस्था का संचालन करता है तथा अन्य बैंकों का नियंत्रण करता है।"

सरल परिभाषा

केन्द्रीय बैंक वह सर्वोच्च बैंक है जो मुद्रा निर्गमन, मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली तथा साख नियंत्रण का कार्य करता है।

2. केन्द्रीय बैंक की विशेषताएँ (Characteristics)

(1) सर्वोच्च बैंक

देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष संस्थान होता है तथा अन्य सभी बैंक इसके नियंत्रण में कार्य करते हैं।

(2) सरकार का बैंक

सरकार के बैंक, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

(3) नोट निर्गमन का एकाधिकार

देश में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार सामान्यतः केवल केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होता है।

(4) लाभ नहीं, आर्थिक स्थिरता उद्देश्य

केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना नहीं बल्कि आर्थिक एवं मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है।

3. केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of Central Bank)

(1) नोट निर्गमन (Issue of Currency)

केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा नोट जारी करता है तथा उनकी आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

(2) सरकार का बैंक (Banker to Government)

सरकार के खाते संचालित करता है, सरकारी भुगतान करता है तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है।

(3) बैंकों का बैंक (Banker's Bank)

वाणिज्यिक बैंक अपने नकद भंडार केन्द्रीय बैंक में रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उससे ऋण प्राप्त करते हैं।

(4) अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort)

संकट की स्थिति में जब अन्य स्रोत उपलब्ध न हों, तब केन्द्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।

(5) साख नियंत्रण (Credit Control)

रेपो दर, CRR, SLR, बैंक दर एवं खुले बाजार परिचालन (OMO) जैसे साधनों द्वारा मुद्रा एवं ऋण की मात्रा नियंत्रित करता है।

(6) विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक

विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण भंडार का संरक्षण करता है तथा विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास करता है।



वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)

1. वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा (Definition)

परिभाषा

वाणिज्यिक बैंक वह बैंक है जो जनता से जमा स्वीकार करता है तथा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण एवं अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

2. वाणिज्यिक बैंक की विशेषताएँ (Characteristics)

(1) जमा स्वीकार करना

बचत, चालू एवं सावधि खातों के माध्यम से जनता से धन जमा करता है।

(2) ऋण प्रदान करना

व्यक्तियों, व्यापारियों एवं उद्योगों को विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है।

(3) लाभ कमाना

इनका प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से लाभ अर्जित करना होता है।

(4) भुगतान प्रणाली विकसित करना

चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, IMPS एवं UPI जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

3. वाणिज्यिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks)

(A) प्राथमिक कार्य (Primary Functions)

(1) जमा स्वीकार करना

जनता की बचत को सुरक्षित रखकर विभिन्न प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करता है।

(2) ऋण प्रदान करना

व्यक्तिगत, कृषि, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है।

(3) साख निर्माण (Credit Creation)

जमा राशि के आधार पर ऋण देकर नई साख का निर्माण करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है।

(B) गौण कार्य (Secondary Functions)

(1) चेक सुविधा

(4) विदेशी विनिमय सेवा

(2) धन हस्तांतरण

(5) एजेंसी सेवाएँ

(3) लॉकर सुविधा

व्याख्या:

वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को भुगतान, संग्रहण, निवेश, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI)

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की परिभाषा

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुई तथा 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य प्रारम्भ किया।

2. RBI का इतिहास (History of RBI)

महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- ✓ अधिनियम – Reserve Bank of India Act, 1934
- ✓ राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- ✓ मुख्यालय – मुंबई (Mumbai)

3. RBI के उद्देश्य (Objectives)

(1) मूल्य स्थिरता बनाए रखना

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मुद्रा की क्रय शक्ति बनाए रखना।

(2) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना

उद्योग, कृषि एवं व्यापार के लिए संतुलित मौद्रिक नीति अपनाना।

(3) वित्तीय स्थिरता

बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय बाजार को सुरक्षित एवं मजबूत बनाना।

4. RBI के प्रमुख कार्य (Functions of RBI)

(1) मुद्रा नोट जारी करना

₹1 के नोट एवं सिक्कों को छोड़कर सभी मुद्रा नोट RBI जारी करता है।

(2) मौद्रिक नीति का संचालन

रेपो दर, रिवर्स रेपो, CRR, SLR तथा OMO के माध्यम से मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करता है।

(3) सरकार का बैंक

केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंक, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

(4) बैंकों का बैंक

सभी अनुसूचित बैंक RBI के पास अपने नकद भंडार रखते हैं तथा आवश्यकता होने पर उससे सहायता प्राप्त करते हैं।

(5) विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है तथा विदेशी विनिमय बाजार में स्थिरता बनाए रखता है।

(6) भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विकास

डिजिटल भुगतान प्रणाली (NEFT, RTGS, UPI आदि) को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने के लिए नियामक की भूमिका निभाता है।

(7) बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षण

बैंकों का लाइसेंस, निरीक्षण एवं नियमन करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

5. RBI की मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण (Monetary Policy Instruments)

मात्रात्मक (Quantitative Instruments)

- ✓ रेपो दर (Repo Rate)
- ✓ रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)
- ✓ बैंक दर (Bank Rate)
- ✓ नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
- ✓ वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- ✓ खुले बाजार परिचालन (Open Market Operations)

गुणात्मक (Qualitative Instruments)

- ✓ नैतिक अनुनय (Moral Suasion)
- ✓ चयनात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Control)
- ✓ प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

6. केन्द्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक में अंतर

आधार	केन्द्रीय बैंक	वाणिज्यिक बैंक
उद्देश्य	आर्थिक स्थिरता	लाभ अर्जित करना
स्वामित्व	सामान्यतः सरकारी	सरकारी/निजी दोनों
ग्राहकों का प्रकार	सरकार एवं बैंक	आम जनता
नोट निर्गमन	करता है	नहीं करता
साख नियंत्रण	करता है	नहीं करता
अंतिम ऋणदाता	हाँ	नहीं
मौद्रिक नीति	बनाता एवं लागू करता है	उसका पालन करता है

(Important Facts)

- ✓ RBI Act – 1934
- ✓ RBI स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- ✓ राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- ✓ मुख्यालय – मुंबई
- ✓ ₹1 का नोट – भारत सरकार जारी करती है।
- ✓ ₹2 एवं उससे अधिक के नोट – RBI जारी करता है।
- ✓ RBI = भारत का केन्द्रीय बैंक।
- ✓ Commercial Bank = Deposit + Loan + Credit Creation.
- ✓ Central Bank = Currency + Credit Control + Monetary Policy.

(Revision Points)

- ✓ Monetary Institutions = मुद्रा एवं साख का संचालन करने वाली संस्थाएँ।
- ✓ Central Bank = बैंकों का बैंक + अंतिम ऋणदाता।
- ✓ Commercial Bank = जनता से जमा स्वीकार कर ऋण देता है।
- ✓ RBI स्थापना = 1 अप्रैल 1935।
- ✓ RBI Nationalisation = 1 जनवरी 1949।
- ✓ RBI Act = 1934।
- ✓ Repo Rate ↑ ⇒ मुद्रा संकुचन।
- ✓ Repo Rate ↓ ⇒ मुद्रा प्रसार।
- ✓ CRR एवं SLR = RBI के प्रमुख मौद्रिक उपकरण।
- ✓ RBI का प्रमुख उद्देश्य = मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक विकास।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त (International Trade Theory)

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) की परिभाषा (Definition)

प्रो. हैबरलर (Gottfried Haberler) के अनुसार

"जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है, तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।"

सरल परिभाषा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) से आशय दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी तथा तकनीक के आदान-प्रदान से है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त (International Trade Theory) की परिभाषा

परिभाषा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त वे आर्थिक सिद्धान्त हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं, किन वस्तुओं का व्यापार करते हैं तथा व्यापार से उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य (Objectives)

(1) संसाधनों का कुशल उपयोग (Efficient Utilization of Resources)

प्रत्येक देश अपने उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। इससे उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादकता बढ़ती है।

उप-बिंदु

- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
- श्रम एवं पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग
- उत्पादन दक्षता

2) विशेषज्ञता (Specialization)

देश उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें उन्हें लागत या उत्पादकता की दृष्टि से लाभ होता है।

व्याख्या:

विशेषज्ञता से उत्पादन बढ़ता है, लागत घटती है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलता है।

(3) आर्थिक विकास

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से निर्यात, विदेशी मुद्रा आय, निवेश एवं रोजगार में वृद्धि होती है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।

(4) उपभोक्ता कल्याण

उपभोक्ताओं को विभिन्न देशों की बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएँ उचित कीमत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्तों का वर्गीकरण

(1) निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त (Absolute Advantage Theory) – एडम स्मिथ

(2) तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त (Comparative Advantage Theory) – डेविड रिकार्डो

(3) हेक्सचर-ओहलिन सिद्धान्त (Heckscher-Ohlin Theory)

भाग-I : एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त

(Adam Smith's Absolute Advantage Theory)

1. परिचय

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एडम स्मिथ (Adam Smith) ने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Wealth of Nations" में किया।

2. परिभाषा

निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त के अनुसार, प्रत्येक देश को उसी वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करना चाहिए जिसमें वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत या कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर सकता हो।

3. मुख्य मान्यताएँ (Assumptions)

(1) दो देश एवं दो वस्तुएँ

सिद्धान्त में केवल दो देशों एवं दो वस्तुओं को माना गया है।

(2) मुक्त व्यापार (Free Trade)

देशों के बीच व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।

(3) उत्पादन लागत स्थिर

उत्पादन लागत एवं तकनीक में परिवर्तन नहीं होता।

(4) श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन

उत्पादन की लागत का आधार केवल श्रम को माना गया है।

4. मुख्य सिद्धान्त (Main Principle)

यदि कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर कर सकता है, तो उसे उसी वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए।

उदाहरण

✓ भारत – कपास

✓ इंग्लैंड – मशीनें

दोनों देश अपनी-अपनी विशेषज्ञता वाली वस्तु का निर्यात करेंगे और दूसरी वस्तु का आयात करेंगे।

5. सिद्धान्त के गुण (Merits)

- (1) श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा।
- (2) उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि।
- (3) संसाधनों का कुशल उपयोग।
- (4) उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।

6. सिद्धान्त के दोष (Criticisms)

- (1) यदि किसी देश को किसी भी वस्तु में निरपेक्ष लाभ न हो, तो यह सिद्धान्त व्यापार की व्याख्या नहीं कर पाता।
- (2) केवल श्रम को उत्पादन का आधार मानना अवास्तविक है।
- (3) परिवहन लागत एवं व्यापारिक बाधाओं की उपेक्षा करता है।

भाग-II : डेविड रिकार्डों का तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त (Ricardo's Comparative Advantage Theory)

1. परिचय

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन डेविड रिकार्डों (David Ricardo) ने 1817 में अपनी पुस्तक "Principles of Political Economy and Taxation" में किया।

2. परिभाषा

रिकार्डों के अनुसार, यदि किसी देश को सभी वस्तुओं में निरपेक्ष लाभ हो, तब भी व्यापार संभव है। प्रत्येक देश को उस वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उसका तुलनात्मक (Comparative) लाभ अधिक हो अथवा अवसर लागत कम हो।

3. मुख्य मान्यताएँ (Assumptions)

- (1) दो देश एवं दो वस्तुएँ
विश्लेषण को सरल बनाने के लिए केवल दो देशों एवं दो वस्तुओं को माना गया।
- (2) श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन
उत्पादन लागत श्रम पर आधारित मानी गई है।
- (3) मुक्त व्यापार
देशों के बीच व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (4) पूर्ण रोजगार
सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग माना गया है।

4. मुख्य सिद्धान्त (Main Principle)

देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसकी अवसर लागत (Opportunity Cost) कम हो।

उदाहरण

यदि भारत कपड़ा एवं चाय दोनों में कुशल है, लेकिन चाय में तुलनात्मक लाभ अधिक है, तो भारत को चाय का निर्यात करना चाहिए।

5. सिद्धान्त के गुण (Merits)

- (1) निरपेक्ष लाभ न होने पर भी व्यापार की व्याख्या करता है।
- (2) अवसर लागत की अवधारणा को महत्व देता है।
- (3) आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना जाता है।
- (4) वैश्विक विशेषज्ञता एवं उत्पादन दक्षता को बढ़ावा देता है।

6. सिद्धान्त के दोष (Criticisms)

- (1) श्रम को एकमात्र उत्पादन साधन मानना उचित नहीं।
- (2) परिवहन लागत की उपेक्षा।
- (3) तकनीकी परिवर्तन एवं पूँजी की उपेक्षा।
- (4) वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार की धारणा अवास्तविक है।

भाग-III : हेक्सचर-ओहलिन सिद्धान्त (Heckscher-Ohlin Theory)

1. परिचय

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एली हेक्सचर (Eli Heckscher) एवं बर्टिल ओहलिन (Bertil Ohlin) ने किया। इसे कारक संपदा सिद्धान्त (Factor Endowment Theory) भी कहा जाता है।

2. परिभाषा

इस सिद्धान्त के अनुसार, कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में उसके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन कारकों (Factors of Production) का अधिक उपयोग होता है तथा उन वस्तुओं का आयात करता है जिनके लिए दुर्लभ कारकों की आवश्यकता होती है।

3. मुख्य मान्यताएँ (Assumptions)

- (1) दो देश, दो वस्तुएँ एवं दो उत्पादन कारक
विश्लेषण में केवल श्रम एवं पूँजी को उत्पादन कारक माना गया है।
- (2) तकनीक समान
दोनों देशों में उत्पादन तकनीक समान मानी गई है।

(3) उत्पादन कारकों की गतिशीलता

देश के भीतर उत्पादन कारक गतिशील हैं, परन्तु देशों के बीच गतिशील नहीं हैं।

(4) मुक्त व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

4. मुख्य सिद्धान्त (Main Principle)

जिस देश में श्रम अधिक उपलब्ध होगा, वह श्रम-प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा।

जिस देश में पूँजी अधिक उपलब्ध होगी, वह पूँजी-प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा।

उदाहरण

✓ भारत → श्रम-प्रधान वस्तुएँ (Textiles, Leather Products)

✓ जापान/जर्मनी → पूँजी-प्रधान वस्तुएँ (Machinery, High Technology Products)

5. सिद्धान्त के गुण (Merits)

(1) उत्पादन कारकों की उपलब्धता के आधार पर व्यापार की व्याख्या करता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन स्वरूप को स्पष्ट करता है।

(3) आधुनिक व्यापार संरचना को समझाने में उपयोगी है।

(4) संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

6. सिद्धान्त के दोष (Criticisms)

(1) तकनीक को समान मानना अवास्तविक है।

(2) वास्तविक व्यापार में परिवहन लागत एवं व्यापारिक बाधाओं की उपेक्षा करता है।

(3) Leontief Paradox इस सिद्धान्त को चुनौती देता है, क्योंकि कुछ पूँजी-समृद्ध देशों ने श्रम-प्रधान वस्तुओं का भी निर्यात किया।

(4) आधुनिक व्यापार में तकनीक, नवाचार एवं मानव पूँजी का पर्याप्त समावेश नहीं है।

7. तीनों सिद्धान्तों में अंतर (Comparison of Trade Theories)

आधार	एडम स्मिथ	डेविड रिकार्डो	हेक्सचर-ओहलिन
प्रतिपादक	एडम स्मिथ	डेविड रिकार्डो	हेक्सचर एवं ओहलिन
आधार	निरपेक्ष लाभ	तुलनात्मक लाभ	उत्पादन कारकों की उपलब्धता
मुख्य विचार	कम लागत में उत्पादन	अवसर लागत कम होना	प्रचुर कारकों का उपयोग
व्यापार का कारण	निरपेक्ष दक्षता	तुलनात्मक दक्षता	Factor Endowment
प्रमुख उत्पादन कारक	श्रम	श्रम	श्रम एवं पूँजी

(Important Facts)

- ✓ 1776 – Adam Smith – The Wealth of Nations.
- ✓ 1817 – David Ricardo – Principles of Political Economy and Taxation.
- ✓ Absolute Advantage = निरपेक्ष लाभ।
- ✓ Comparative Advantage = तुलनात्मक लाभ।
- ✓ Heckscher–Ohlin = Factor Endowment Theory (कारक संपदा सिद्धान्त)।
- ✓ Ricardo → Opportunity Cost (अवसर लागत) पर आधारित व्यापार।
- ✓ Heckscher–Ohlin → श्रम-प्रधान एवं पूँजी-प्रधान वस्तुओं का व्यापार।
- ✓ Leontief Paradox → Heckscher–Ohlin सिद्धान्त की प्रमुख आलोचना।

(Revision Points)

- ✓ Adam Smith = Absolute Advantage Theory (1776).
- ✓ David Ricardo = Comparative Advantage Theory (1817).
- ✓ Heckscher–Ohlin = Factor Endowment Theory.
- ✓ Absolute Advantage → कम लागत में उत्पादन।
- ✓ Comparative Advantage → कम अवसर लागत।
- ✓ H–O Theory → प्रचुर उत्पादन कारक वाली वस्तु का निर्यात।
- ✓ Leontief Paradox = H–O सिद्धान्त की चुनौती।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार = विशेषज्ञता, तुलनात्मक लाभ एवं संसाधनों का कुशल उपयोग।

Unleash the topper in you